राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 11.12.2013 को आयोजित 119वीं बैठक के कार्यवृत

बैठक की अध्यक्षता श्री पी.श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गई। बैठक में श्री जे.के.बागडी, महाप्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमती टी.एस.राजीगेन महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्रीमती रश्मि शर्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर(LP & SHGs) राजस्थान सरकार, तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारिगण, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों द्वारा सहभागिता की गई। (सूची संलग्न है)

श्री एल.एम.अस्थाना, संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय से उनके उदबोधन हेतु आग्रह किया गया।

श्री पी.श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए बताया कि राज्य मे कार्यरत बैंकों द्वारा विभिन्न पैरामीटर्स तहत संतोषप्रद उपलब्धि दर्ज की गई है। राज्य में साख-जमा अनुपात उच्च रहते हुए 98.18% रहा, जो राज्य में अग्रिम तथा जमा दोनों ही क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के साथ उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रथम छमाही में उपलब्धि 62% रही। सितम्बर, 2013 को राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि तथा कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिमों का स्तर निर्धारित बैंचमार्क से कहीं अधिक रहा।

उन्होने बताया कि राज्य मे कृषि ऋणों में वृद्धि हेतु अपार सम्भावनाऐं है तथा एग्रीकल्चर इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Soil & Water Conservation, Horticulture Plantation हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता है व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को डेबिट कार्ड/ए.टी.एम कार्ड शीघ्र जारी करने पर बल दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) स्कीम के क्रियांवयन हेतु चिन्हित जिलों यथा अजमेर,अलवर,उदयपुर,झुंझुनू, कोटा तथा पाली मे कार्यरत सभी शाखाओं मे शीघ्रतिशीघ्र ए.टी.एम.स्थापित किया जाना तथा DBT जिलों मे आंवटित अंबैक्ट एस.एस.ए.(Unbanked SSAs) मे बैकिंग आउटलेट स्थापित किया जाना तत्परता से पूर्ण कर लेना चाहिये ।

DBT/DBTL लाभार्थियों के आधार नम्बर संग्रहित करने व आधार सीडिंग का उचित मैकिनिज्म/सिस्टम (Mechanism/System) बनाये जाने तथा आधार सीडेड (Seeded) खातों की जानकारी नियमित आधार पर NPCI Mapper पर अपडेट करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

उन्होने सदन को अवगत करवाया कि नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में राज्य में कार्यरत्त बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज का अच्छा कार्य किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के गठन, बैंक लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज सततरुप से (Continuous Basis) करने की आवश्यकता बताई।

अध्यक्ष महोदय ने सरकारी योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 28.02.2014 तक सुनिश्चित किये जाने के लिये जोर दिया ।

राज्य मे बडी संख्या मे बकाया **RODA Cases** के मध्यनजर सरकारी विभागों को वसूली का माहोल पैदा करने तथा वसूली मे बैकों को सहयोग देने पर बल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य विकासपरक मुद्दों पर आज की बैठक के कार्यसूची में विस्तृत चर्चा की जावेगी। अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

तत्पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 118 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

(i) **To facilitate banks to create online charge on agriculture land for extending agriculture credit to farmers** :-
कृषि भूमि पर बैंक का प्रभार ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा बैंकों को उपलब्ध करवाने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से पुन: अनुरोध किया गया ।

<u>(कार्यवाही: राजस्व विभाग)</u>

(ii) **Setting up of brick & mortar branch/6days ultra small branch in all FI villages having population>5000 in under banker district & > 10000 in other district-** सदन को अवगत करवाया गया कि शाखाएं/6 Days USB खोलने के लिये 138 गांवो को चिन्हित किया गया है जिनमे से 137 केन्द्रो पर शाखाएं/6 Days USB खोल दी गई है । शेष रहे -1- केन्द्र पर शाखा/6 Days USB खोलने के बारे मे SBBJ को आवश्यक कदम उठाना है ।

(iii) Sub Service Area Approach- Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSC :Banks to ensure coverage of all unbanked sub service area (SSA)

राज्य की सभी 9091 ग्राम पंचायत में 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) चिन्हित किए गए है,जिनमें से 4923 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) बैंक शाखा/बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा चुके है। इनमे 2051 वर्तमान शाखाओं द्वारा,2373 BCA द्वारा,448 CSC द्वारा व 51 अन्य माध्यमों द्वारा कवर किये गये है ।

DBT जिलों मे 2037 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) चिन्हित किए गए है, जिनमें से 1629 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) बैंक शाखा/बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा चुके है। बैंको को आवंटित शेष 4483 unbanked SSAs को शीघ्र कवर करने का आग्रह किया गया तथा इसमे DBT जिलों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(iv) Updation of GIS Data: DCC Convener Banks are requested to ensure updation of GIS data on GIS Portal by LDMs : इस सन्दर्भ मे समय-समय पर SLBC द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किये गये है । सभी डी.सी.सी.समंवयक(Convener)बैको को यह सुनिश्चित करना है कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा GIS Portal पर सूचनाएं नियमित आधार पर Update की जा रही है। सदस्य बैंकों को राज्य मे स्थापित की गई नई शाखा, ए.टी.एम. व बी.सी.की सूचनाये नियमित तौर पर LDMs को अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया जिससे LDM स्तर पर GIS Portal मे इन सूचनाओं को अद्धतन किया जा सके।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(v) Installation of onsite ATM :राज्य मे कार्यरत 5889 शाखाओं मे से 2615 शाखाओं मे onsite ATM है। वाणिज्यिक बैकों व ग्रामीण बैकों द्वारा 2013-14 के दौरान 1063 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

(vi) Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन हेतु पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2:</u>

शाखा विस्तार: राज्य में 30.09.2013 को कुल 5889 बैंक शाखाएँ कार्यरत्त है। चालू छमाही के दौरान खोली गई 156 शाखाओं में से 141 (91%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गई। बैंक शाखाओं के अतिरिक्त, सितम्बर,2013 को राज्य में कुल 4707 ए.टी.एम. एवं 3515 बी.सी. एजेण्ट कार्यरत्त है।

जमाएँ व अग्रिम: सितम्बर,2013 को राज्य में कुल जमाएँ रूपये 203197 करोड़ तथा कुल अग्रिम रूपये 193027 करोड़ रहा ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में YOY वृद्धि 26.91% रही। वहीं कृषि में 23.63%, सूक्ष्म व लघु क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 31.44% तथा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण में 31.25% दर्ज की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण में उत्तरोत्तर वृद्धि किए जाने पर जोर दिया गया।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): सितम्बर, 2013 को राज्य में साख जमा अनुपात 98.18% रहा। जिला स्तर पर 8 जिलों का साख जमा अनुपात 100% से अधिक रहा, वहीं 24 जिलों में यह अनुपात 50%-100% के मध्य व 1 जिले मे यह अनुपात 50% से नीचे रहा है।

अध्यक्ष महोदय तथा श्री जे.के.बागडी, महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक, ने सभी बैकों से इस ओर आवश्यक कदम उठाने व CD Ratio मे सुधार करने का आग्रह किया ।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों(वार्षिक) के सापेक्ष सितम्बर छमाही मे उपलब्धि 62% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 62%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 102%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 39% की उपलब्धि दर्ज की गई।

महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि कृषि क्षेत्र मे रिपोर्टिंग फार्मेट को अल्पावधि ऋण, दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किया जाये जिससे कि समुचित रुप मे निगरानी की जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न प्रत्यक्ष कृषि/अप्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र मे ऋण प्रवाह मे वृद्धि पर बल दिया तथा ग्रामीण गोदाम जैसी योजना पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 3-</u>

3.1 Under Banked/Unbanked District/Blocks : Branch Authorization Policy: भारतीय रिजर्व बैंक ने Domestic Scheduled Commercial Banks(Other than RRBs) को RBI की पूर्वानुमति बिना शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की है,बशर्त इसकी रिपोर्टिंग RBI को की जाये तथा निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाये :-

- वित्तीय वर्ष के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं मे से 25% शाखायें अनबैक्ट्ड(Unbanked) ग्रामीण केन्द्रो(Tier 5 and 6) अर्थात जहाँ ग्राहक आधारित बैकिंग लेनदेन के लिये किसी Scheduled Commercial Bank की Brick & Mortar Structure न हो ।
- वित्तीय वर्ष के दौरान Tier-1 केन्द्रों पर खोली गयी शाखाएं Tier-2 से Tier-6 केन्द्रों पर खोली गयी शाखाओं से अधिक नही हो ।

(कार्यवाही-सदस्य-बैक)

To open branch/6days ultra small branch in villages with population 5000 & above in under banked district & 10000 & above in other district-

सदन को अवगत करवाया गया कि शाखाएं/6 Days USB खोलने के लिये 138 केन्द्रो को चिन्हित किया गया है जिनमे:

- Under Banked District के 5000 व अधिक जनसंख्या वाले 136 केन्द्र तथा,
- अन्य जिलों के 10000 व अधिक जनसंख्या वाले -2- केन्द्र चिन्हित किये गये ।

इनमे से 137 केन्द्रो पर शाखाएं/6 Days USB खोल दी गई है । शेष रहे -1- केन्द्र पर शाखाएं/6 Days USB खोलने के बारे मे SBBJ को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी ।

(कार्यवाही: एस.बी.बी.जे.)

Direct Benefit Transfer (DBT)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अनुरोध किया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की **DBT** स्कीम के तहत चिन्हित 6 जिलो यथा अजमेर,अलवर,उदयपुर,झुंझुनू,कोटा तथा पाली मे चिन्हित लाभार्थियों के खाते खोले व खाता धारकों के बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये।

Direct Benefit Transfer for LPG (DBTL)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा DBTL योजना के क्रियांवयन के लिये राज्य सरकार/नोडल विभाग द्वारा लाभार्थियों की सूची आवश्यक जानकारी यथा बैंक खाता नम्बर,आधार सीडिंग इत्यादि उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया, जिससे बैक खाते मे आधार सीडिंग किया जाकर DBTL का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध मे बताया कि :-

- बैकों को यह देखना है कि आधार सीडिंग का डाटा **NPCI** पर नियमित आधार पर Upload किया जा रहा है।
- DBT के सफल क्रियांवयन के लिये सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको को नोडल विभाग से समंवय रखा जाये ।
- ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली सूची के अतिरिक्त बैक शाखाओं द्वारा LPG लाभार्थियों से सीधे आधार नम्बर प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाये ।

(कार्यवाही-सदस्य बैक)

Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs for Direct Cash Transfer – Sub Service Area Approach:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सदन को अवगत करवाया कि MOF GOI के निर्देशानुसार जनसंख्या व दूरी के आधार पर राज्य मे कुल 9091 ग्राम पंचायतों मे 9406 SSAs चिन्हित किये गये है तथा बैकों को आवंटित किये गये है।

- 4923 SSAs अब तक कवर किये जा चुके है जिनमे 2051 वर्तमान बैक शाखाओं द्वारा, 2373 BCs द्वारा व 448 CSCs द्वारा तथा 51 SSAs अन्य Mode द्वारा कवर किये गये है।
- DBT जिलों मे कुल 2037 SSAs मे से 1629 कवर किये गये हैं ।
- **संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा** अनुरोध किया गया है कि आंवटित SSA मे बैंक शाखा/ BCA की नियुक्ति की जावे।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

Development of MIS reporting System for creation of SSAs and monitoring progress in extension of banking facilities in the SSAs:

MOF GOI द्वारा SSA की पुर्ण जानकारी हेतु **MIS** पोर्टल विकसित किया गया है । प्रथम चरण मे PILOT आधार पर अग्रणी जिला उदयपुर को इस पोर्टल पर SSA की सुचनाये अद्धतन करने हेतु चिन्हित किया गया । अब सभी अग्रणी जिला प्रबन्धको को SSA की सुचनाये अधतन करने हेतु यह पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है।
अग्रणी जिला प्रबन्धक उदयपुर ने **MIS** पोर्टल पर डाटा अपडेशन पुर्ण कर लिये जाने से सूचित किया है।

Roadmap for providing banking services in villages<2000 -

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा इस विषय मे हुई प्रगति कि जानकारी सदन को दी गयी :-
2000 से कम आबादी वाले 35085 गांवो मे से सितम्बर,13 तक 7575 गांवों को कवर किया गया है। इसमे SSA Approach के तहत 1671 गांवों को वर्तमान बैंक शाखाओं द्वारा व 5858 गांवों को वर्तमान BCs द्वारा तथा 46 गांवों को नई शाखाओं द्वारा कवर किया गया है।

श्री जे.के.बागडी, महाप्रबन्धक , भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय मे बताया कि :
-किसी गांव मे बैक शाखा या BC आउटलेट की fixed location होने तथा BC द्वारा पूर्व निर्धारित दिवस पर उस गांव मे विजिट कर बैकिंग सेवाये उपलब्ध करवाये जाने पर ही उस गांव को कवर किया जाना माना जायेगा ।
-उन्होंने पर्याप्त व्यवसाय के अवसर पैदा करने हेतु BC को प्रोत्साहित(Motivate) करने के लिये कहा।

Urban Financial Inclusion:
इस सम्बन्ध मे सदन को अवगत करवाया गया कि :-
- सभी जिलों मे अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा बैकों को वार्ड (Wards) आंवटित किये गये है।
- शाखाओं को सेवा क्षेत्र के गांवों व आंवटित किये गये वार्डो मे प्रति परिवार एक व्यक्ति का खाता खोला जाना है।

Installation and Managed Services of Cash Dispensers (CDs):

- संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा DBT जिलों मे सभी शाखाओं मे Onsite ATM स्थापित किये जाने तथा ATM Cum Debit Card जारी किये जाने के लिये कहा गया ।

- उन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 1063 ATM स्थापित किया जाना प्रस्तावित होने से अवगत करवाया ।

Use of NOFN (National Optical Fibre Network) Infrastructure in Rural Branches of PSBs and RRBs:

- अरेन (Arain) ब्लॉक जिला अजमेर को इसके लिये Pilot Basis पर चयनित किया गया है तथा इस ब्लॉक के सभी 30 ग्राम पंचायतों को NOFN से जोडा गया है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी ने अवगत करवाया कि NOFN के उपयोग पर चर्चा के लिये DFS MOF ने Pilot Blocks के संयोजक, एस.एल.बी.सी. के साथ दिनांक 12.11.2013 को विडियो कॉंफ्रेंस (Vedio

conference) रखी जिसमे महाप्रबन्धक BSNL ने भी भाग लिया जिसमे अरेन (Arain) ब्लॉक मे स्थापित व स्थापित की जानी वाली शाखाओं मे निर्बाध/सुचारु कनेक्टिविटी हेतु NOFN के उपयोग की संभावनाये जांचने हेतु अनुरोध किया गया।

Uploading of GIS data:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि GIS Portal पर बैंकों से सम्बन्धित उपलब्ध जानकारी यथा नई शाखा/करेंसी चेस्ट, नियुक्त बीसी. एजेण्ट, नए स्थापित ए.टी.एम. इत्यादि अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा अपडेट रखनी है। नियमित अपडेशन के लिये जिले मे स्थित सभी बैको द्वारा उक्त जानकारियां अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाया जाना अहम है।

डी.सी.सी. संयोजक बैंक से अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा GIS Portal पर मासिक आधार पर सूचनाओं को अद्यतन करवाना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

एजेण्डा क्रमांक – 4:

Agriculture Credit Flow: वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सितम्बर 2013 तक कुल 13.62 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए तथा योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 102.78 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके है जिनमें एक्टिव कार्डो की संख्या 75.80 लाख रही ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि राज्य मे कृषि ऋणों में वृद्धि हेतु अपार सम्भावनाऐं है तथा एग्रीकल्चर इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Soil & Water Conservation, Horticulture Plantation हेतु विशेष बल देने की आवश्यकता है व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को डेबिट कार्ड/ए.टी.एम कार्ड शीघ्र जारी करने पर बल दिया ।

ग्रामीण भण्डारण योजना :

सदन को अवगत करवाया गया कि नाबार्ड के परिपत्र दिनांक 23.08.13 के अनुसार कॉमन वाल (Common Wall) के साथ निर्मित गोदाम भी इस योजना तहत अनुदान के योग्य होंगे ।

श्रीमती टी.एस.राजीगेन महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अनुदान दावे पुर्ण सूचनाओं के साथ प्रस्तुत किये जाने का आग्रह किया जिससे कि निस्तारण शीघ्रता से हो सके ।

एजेण्डा क्रमांक – 5:Government Sponsored Schemes:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया कि 01.04.2013 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-NRLM [National Rural Livelihood Mission] में विलय हो

चुका है, तथा 01.04.2013 NRLM योजना प्रभावी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि NRLM योजना तहत केपिटल सब्सिडी देय नही है।

नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने स्वयं सहायता समूह को प्रथम डोज(First Dose) के रुप मे कम से कम रु.50000/- का ऋण उपलब्ध करवाये जाने का अनुरोध किया ।

श्रीमती रश्मि शर्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर(LP & SHGs) राजस्थान सरकार ने सदन को अवगत करवाया कि नाबार्ड द्वारा SHG कार्यक्रम को गति देने हेतु विभिन्न प्रारूप तथा ऋण हेतु Common आवेदन पत्र हेतु अनुमोदित प्रारूपों को बुकलेट (पुस्तिका) के रूप में संकलित कर सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाया गया है। अतः सभी बैंक शाखाओं को समानता बनाये रखने के लिये इन अनुमोदित प्रारूपों को उपयोग मे लिया जाना चाहिये ।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): योजना अंतर्गत 2013-14 के लिए 8000 लाभार्थियो को लाभांवित्त करने के लक्ष्य बैको को दिया गया है,जिसके तहत सितम्बर छमाही मे कुल 10517 आवेदन पत्रो मे से 1991 मे स्वीकृत्तियां जारी की गयी तथा 1159 मे ऋण वितरण किया गया ।

परियोजना निदेशक (SJSRY) ने लम्बित आवेदन पत्र के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के तहत वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 28.02.2014 तक कर लिये जाने का सभी बैकों से अनुरोध किया ।

प्रधामंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): सदन को अवगत करवाया गया कि योजना अंतर्गत 2013-14 तहत सितम्बर छमाही तक कुल 2804 आवेदन पत्रो मे से 323 मे स्वीकृतिया जारी की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रायोजित एजेंसियो से आंवटित लक्ष्यों के मध्यनजर क्षेत्रवार/जिलेवार पर्याप्त आवेदन पत्र प्रायोजित किये जाने हेतु आग्रह किया तथा प्राप्त आवेदन पत्रो को शीघ्रता से निस्तारित करने के लिये बैकों को निर्देशित किया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत करवाया गया कि कि e-tracking portal का Access हेतु बैक शाखा का IFSC CODE युजर आईडी होगा तथा small letter मे "pmegp"प्रथम बार पासवर्ड होगा,इसके पश्चात पासवर्ड बदला जा सकेगा। उन्होंने PMEGP तहत प्राप्त सभी आवेदन पत्रो के निस्तारण सम्बन्धी विवरण e-tracking portal पर Update रखने हेतु बैकों से अनुरोध किया ।

Micro, small and Medium Enterprises (MSME): सभी सदस्य बैंकों से RBI द्वारा निर्धारित बैंचमार्क की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास हेतु अनुरोध किया गया।

Special Central Assistance Scheme for SC/ST: सदन को अवगत करवाया गया कि योजना अंतर्गत 2013-14 के लिए 30620 लाभार्थियो को लाभांवित्त करने के लक्ष्य बैको को दिया गया है,जिसके तहत अक्टूबर,13 तक कुल 4039 आवेदन पत्रो मे स्वीकृतिया जारी की गयी ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रो के शीघ्र निस्तारण तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आग्रह किया गया ।

Self Help Groups (SHG): सदन को अवगत करवाया गया कि सितम्बर छमाही के दौरान राज्य में 7049 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज किया गया तथा 4255 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है। SHG बैंक/क्रेडिट लिंकेज हेतु अनुमोदित Common आवेदन पत्र एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है।

भारत सरकार की पिछड़े जिलों यथा बाडमेर,बांसवाडा,डूंगरपुर,झालावाड में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन योजना के तहत राज्य में वर्ष 2013-14 के लिये 3600 SHGs का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सितम्बर,2013 तक कुल 1891 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया तथा 1910 समूहों का बैंक लिंकेज किया गया है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने योजना के तहत मार्च,2013 तक बैंक लिंकेज किये गये समूहों को क्रेडिट लिंकेज करने की कार्यवाही करने का बैंकों से अनुरोध किया ।

सदन को यह भी अवगत करवाया गया कि **2013-14 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग** द्वारा राज्य मे महिला स्वयं सहायता समूह के लिये राज्य मे संचालित 50% ब्याज अनुदान व एक मुश्त अनुदान योजना के तहत चालू वर्ष के दौरान वित्त पोषित महिला स्वयं सहायता समूह के योजनानुसार अनुदान क्लेम सम्बन्धित नोडल शाखा को तुरंत प्रस्तुत किये जाने चाहिये जिससे कि योजना अंतर्गत हुई प्रगति परिलक्षित हो सके ।

Credit Flow to Minority Community: सदन को अवगत करवाया गया कि सितम्बर छमाही के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को प्रद्त्त ऋणो मे रूपये 774.63 करोड़ की वृद्धि हुई तथा राज्य में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में से अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण का प्रतिशत सितम्बर, 13 को 6.32% रहा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ओर प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 6: Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):
2013-14 के लिए 15950 लाभार्थियो को प्रशिक्षण देने के लक्ष्यों मे से 12689 व्यक्तियों को सितम्बर छमाही के दौरान बैको को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिनमे से 65% प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा

रोजगार प्राप्त किया गया । **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** ने प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों से प्रर्याप्त साख सुविधा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को सुचित किया गया कि राज्य के सभी 33 जिलों में RSETI/RUDSETIs की स्थापना की जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय ने भू-आंवटन तथा भवन निर्माण के सम्बन्ध मे RSETI/RUDSETIs को जिला स्तर पर आ रही कठिनाईयों बाबत शीघ्र निस्तारण के लिये सम्बन्धित विभाग,राजस्थान सरकार को राज्य स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया ।

श्रीमती रश्मि शर्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर(LP & SHGs) राजस्थान सरकार द्वारा इस विषय मे राज्य स्तर से शीघ्र समाधान का सदन को विश्वास दिलाया ।

Financial Literacy Centers (FLCs):

राज्य के सभी 33 जिलों में एफ.एल.सी.सी. की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान मे राज्य मे कुल 46 **FLCs** द्वारा न केवल केन्द्र पर आने वाले व्यक्तियों को बल्कि समय-समय पर जागरुकता कैम्प,रात्री चौपाल व बैठकों के माध्यम से भी एक बडे वर्ग को केन्द्र के उद्देश्य की जानकारी के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता मुहैया करवायी जा रही है।

वित्तीय साक्षरता को बढावा देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार सामग्री यथा वित्तीय साक्षरता गाइड, डायरी एवं 16-वित्तीय साक्षरता पोस्टर जारी किये गये हैं, जिसका ग्रामीण शाखा तथा FLCs द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता कैम्प के दौरान मानक पाठ्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाना है।

वित्तीय साक्षरता प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग में एकरूपता व सभी हितधारकों को वितरण की कार्यवाही एस.एल.बी.सी. द्वारा किए जाने से सूचित किया गया है। वित्तीय साक्षरता प्रचार सामग्री के प्रिंटिंग एवं वितरण के खर्चों की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा वित्तीय साक्षरता फण्ड (FIF) के माध्यम से की जावेगी।

वित्तीय साक्षरता प्रचार सामग्री की आवश्यकता का एस.एल.बी.सी. द्वारा आंकलन कर अनुमोदन हेतु नाबार्ड को प्रेषित किया गया तथा नाबार्ड द्वारा इसका In-principle अनुमोदन किया जा चुका है। प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग तथा वितरण की कार्यवाही हेतु कोर ग्रुप कमेटी का गठन किया गया है । इस कमेटी के निर्णय अनुसार SLBC द्वारा प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग के लिये Re- Tendering की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE</u>:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य में 388 करोड़ के 5266 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण</u>: चालू वित्त वर्ष 2013-14 के लिये MOF द्वारा निर्धारित 73637 खातों मे कुल बकाया राशि रु.1698.55 करोड के लक्ष्यों के पेटे प्राप्ति(Achievment) 62519 खातों में बकाया राशि रु.1437.80 करोड रही ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 9: Interest Subsidy Scheme for Housing Urban Poor (ISHUP):</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा योजना के 30.09.2013 को बन्द होने तथा इसके स्थान पर 01.10.2013 से **"राजीव ऋण योजना"(Rajiv Rinn Yojana)** प्रारम्भ होने से सूचित किया गया ।

राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री के.सी.आहूजा ने ISHUP तहत अनुदान के बकाया प्रकरणों मे शीघ्र अनुदान क्लेम (Claim)प्रस्तुत करने के लिये बैको से आग्रह किया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक–10: वसूली:</u>

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि 30.09.13 को राज्य मे **64662 मामले** वसूली हेतु **RACO ROD Act के** तहत बकाया हैं ।

NPA के उच्च स्तर को देखते हुये **अध्यक्ष महोदय ने** राज्य सरकार के अधिकारियों से संयुक्त वसूली Compaign आयोजित करने का आग्रह किया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 11: SLBC Website:</u> सभी बैंक सदस्यों से तिमाही समाप्ति के 15 कार्य दिवस में आवश्यक सूचना/आंकड़ो को एस.एल.बी.सी. वेबसाइट पर अपलोड किए जाने का अनुरोध किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक – 12-अन्य मामले-</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा अंत में सभी सदस्यों से पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड जारी करने, बैको की सभी शाखाओं मे ऑन साइट एटीम (ATM) स्थापित करने, सेवा क्षेत्र गांवों का Sub Service Area के आधार पर कवरेज करने, अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण में उत्तरोत्तर वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 11.12.2013 को आयोजित 119वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची</u>

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
संयोजक बैंक			
1	श्री पी.श्रीनिवास	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ बड़ौदा
2	श्री एल एम अस्थाना	संयोजक, एस.एल.बी.सी.राजस्थान एवं महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा
भारतीय रिजर्व बैंक			
1	श्री जे.के.बागड़ी	महाप्रबन्धक आर.पी.सी.डी.	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री जय प्रकाश	सहायक महाप्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
नाबार्ड			
1	श्रीमती टी.एस.राजिगेन	महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
2	श्री राजीव सिवाच	उप महाप्रबन्धक	नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि			
1	श्रीमती रशमी शर्मा	पीडी (एलपी और एसएचजी)	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान सरकार
2	श्री एस.आर.कटेवा	परियोजना निदेशक (एस.जे.एस.आर.वाई)	स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार
3	श्री एस.एस.छिलर	निदेशक	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
4	शीला के.चौधरी	उप निदेशक	निदेशालय, एम.एस.एम.ई,जयपुर
5	डा. शीतल शर्मा	अतिरिक्त निदेशक	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
6	डॉ.जी.वी.सिंह	अतिरिक्त निदेशक	कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
7	श्री वी.पी.मिश्रा	ARO	डायरेक्ट्रेट ऑफ हॉर्टिकल्चर,जयपुर
8	श्री आर. के. अमेरिया	संयुक्त निदेशक	आयुक्त उद्योग
9	श्री एल.सी.जैन	अतिरिक्त निदेशक	उद्योग विभाग राज.सरकार,जयपुर
10	श्री आर.के.लाम्बा	संयुक्त निदेशक	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
11	श्री एस.सी.डालोदिया	FA & CAO	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
12	श्री वी.पी.सिंहल	क्षेत्रीय निदेशक	अनु.जाति-जनजाति राष्ट्रीय आयोग, जयपुर
13	श्री के.सी.वर्मा	प्रबन्ध निदेशक	प्रबन्ध निदेशक, अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम, जयपुर
14	श्री एम.पी.मीना	प्रबन्धक	आर.एस.सी.डी.सी.
15	राजेश अरोडा	सहायक	RSCSTFDCl

16	श्री पी.आर.मीणा	AAO	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि.राजस्थान सरकार
17	श्री बी.एस.जाट	ज्वाइंट सेक्रेटरी प्लानिंग	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
18	एम.अरोडा	AD SHG,DWE	महिला एवं बाल विकास विभाग,राज.सरकार
19	श्री सी.एम.ठनियाल	एस.ओ.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम
20	डॉ.प्रतीभा सिंह	ज्वाइंट सेक्रेटरी	Tribal Area Dev.जयपुर
21	श्री जे.एस.नागपाल	महाप्रबन्धक	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड
22	श्री के.सी. आहुजा	सलाहकार	राजस्थान आवास विकास एवं इंफ्रास्ट्रकचर लिमिटेड
23	श्री आर.ए.शर्मा	संयुक्त निदेशक	आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार

बैंक, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम	पद	विभाग/संस्था/बैंक
1	श्री एस.एस.नेगी	महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2	श्री एन.के.अरोरा	महाप्रबन्धक	पंजाब नेशनल बैंक
3	श्रीमती अल्का गोतम	महाप्रबन्धक	अपेक्स को-आपरेटिव बैक जयपुर
4	डॉ. एम.एस.फोगाट	अध्यक्ष	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5	श्री सुधीर ठाकुर	अध्यक्ष	मरूधरा ग्रामीण बैंक
6	श्री एस.एस.शर्मा	महाप्रबन्धक	मरूधरा ग्रामीण बैंक
7	श्री आर.के.गुप्ता	उप महाप्रबन्धक	बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर
8	श्री अलख निरंजन	उप महाप्रबन्धक	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9	श्री नवलीन कुन्द्रा	उप महाप्रबन्धक	ऑरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
10	श्री फरीद अहमद	उप महाप्रबन्धक	कॉर्पोरेशन बैंक
11	एस.के.गोयल	उप महाप्रबन्धक	सिंडिकेट बैंक
12	श्री सी.एल.भावल	उप महाप्रबन्धक	सिडबी
13	श्री परवेश कपूर	उप महाप्रबन्धक	इंडियन ऑवरसीज बैंक
14	श्री मुनेन्द्र सिंह	उप अंचल प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
15	श्री एच.एल.रावल	उप महाप्रबन्धक	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
16	श्री विवेक कौल	सहायक महाप्रबन्धक	युको बैंक
17	श्री आर.के.काला	सहायक महाप्रबन्धक	एस.एल.बी.सी., बैंक ऑफ बड़ौदा
18	श्री जी.एल.महावल	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
19	श्री माधो राम	सहायक महाप्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
20	श्री डी.पी.सिंह	सहायक महाप्रबन्धक	आन्ध्रा बैंक

21	श्री जे.पी.मीना	सहायक महाप्रबन्धक	आई.डी.बी.आई. बैंक
22	श्री फुलवार सिंह	सहायक महाप्रबन्धक	विजया बैंक,क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर
23	श्री जी.जी.अग्रवाल	मुख्य प्रबन्धक	कॉर्पोरेशन बैंक
24	श्री डी.पी.माथुर	मुख्य प्रबन्धक	इलाहाबाद बैंक
25	श्री प्रकाश छबडिया	डिविजनल मैनेजर	केनरा बैक
26	श्री.जे.के.शर्मा	ED(F)	राजस्थान वित्त निगम
27	श्री पी.के.अग्रवाल	मुख्य प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावेन्कोर
28	श्री आर.जे.एस.बक्शी	मुख्य प्रबन्धक	पंजाब & सिन्ध बैंक
29	श्री राजेश इंगला	मुख्य प्रबन्धक	बैंक ऑफ इंडिया
30	श्री एम.आर.मीणा	मुख्य प्रबन्धक	इण्डियन बैक
31	श्री हर्ष मेहता	मुख्य प्रबन्धक	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
32	श्री एस.एम.व्यास	जोनल मैनजर	देना बैंक
33	श्री ईश्वर सिंह शेखावत	अंचल समंवयक	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
34	श्री जितेन्द्र शुक्ला	क्षेत्रीय हैड एफ.आई.	आई. सी. आई. सी. आई. बैंक
35	श्री सन्दीप ठाकुर	डी.वी.पी.	एक्सिस बैंक
36	सुश्री पारूल शर्मा	नोडल अधिकारी	एच.डी.एफ.सी. बैंक
37	श्री रविन्द्र सारदा	वाइस प्रेसीडेण्ट	एच.एस.बी.सी. जयपुर
38	श्री बी.सी. जैन	वरिष्ठ प्रबन्धक	एस.एल.बी.सी., बैंक ऑफ बड़ौदा
39	श्री पी.पी.सिंह	सी.आर.एम.	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
40	श्री जैशन टी. जे.	वरिष्ठ प्रबन्धक	कैथोलिक सिरियन बैंक
41	श्री एस.मिश्रा	वरिष्ठ प्रबन्धक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
42	श्री आर.के.मीणा	वरिष्ठ प्रबन्धक	केनरा बैक
43	डॉ.राजेश	वरिष्ठ प्रबन्धक	देना बैंक
44	श्री एस.राजेश	वरिष्ठ प्रबन्धक	करुर वैश्य बैंक
45	श्री के.डी.खान	वरिष्ठ प्रबन्धक	सिंडिकेट बैंक
46	श्री सुधीर के.बंशल	GM.SLDB	राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक
47	श्री आर.सी.शर्मा	वरिष्ठ प्रबन्धक	राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक
48	श्री हर्ष अग्रवाल	वरिष्ठ प्रबन्धक	स्टेण्डर्ड चार्टेड बैंक
49	श्री मनोज	वाइस प्रेसीडेण्ट	कोटक बैंक
50	श्री डोन बासव	प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
51	श्री अशोक कटारा	प्रबन्धक	मेवाड़ आँचलिक ग्रामीण बैंक
52	श्री आर.एस.राठोड	प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
53	अमरीता डी.	प्रबन्धक	इण्डियन ओवरसीज बैक
54	श्री आरती दीक्षित	सहायक प्रबन्धक	साऊथ इंडियन बैंक
55	श्री हरकेश	उप प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

56	उपेन्द्र वी.	शाखा प्रबन्धक	कोटक बैंक
57	श्री अमित कुमार	शाखा प्रबन्धक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
58	श्री थोमस टी.एम.	शाखा प्रबन्धक	फेडरल बैक जयपुर
59	श्री हरिन्द्र सिंह	अधिकारी	पंजाब & सिन्ध बैंक
60	श्री उमेश शाह	कंल्सटर सैल्स मैनेजर	रत्नाकर बैंक
61	श्री समीर	AAO	भारतीय बीमा निगम,जयपुर्
62	श्री के.प्रसाद	उप प्रबन्धक	भारतीय कृषि बीमा कंपनी,जयपुर
63	केशरदास	रीजनल मैनेजर	न्यु इण्डिया एस्योरेंश कम्पनी
64	जे.सी.शर्मा	व.डिवि.मैनेजर	न्यु इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी
65	एम.महर्षि	व.शाखा प्रबन्धक	न्यु इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी
66	जी.एच.बसु	प्रबन्धक	युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी,जयपुर्
67	आरिफ अंसारी	एड.अधिकारी	युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी,जयपुर्

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx